



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Handwritten signature/initials and date 24/12/88

सं० 630] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 1988/अग्रहायण 18, 1910
No. 630] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 1988/AGRAHAYANA 18, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन की रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1988

सा.का.नि. 1158 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना की तारीख को हरियाणा राज्य में यथा प्रवृत्त पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का हरियाणा अधिनियम सं. 24) का विस्तार, निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर करती है, अर्थात् :

उपान्तरण

1. धारा 2 के आरम्भिक अंश में "पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918" शब्दों और अंकों के स्थान पर चंडीगढ़

संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब न्यायालय अधिनियम 1918 या" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. धारा 4 का शेष किया जाएगा।

3. धारा 5 में की आरम्भिक शक्तियों में, "जीर 4" शब्द और अंक का शेष किया जाएगा।

उपान्तरण

पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का हरियाणा अधिनियम सं. 24) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक यथा प्रसारित

हरियाणा राज्य में लागू की जाने के लिए पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 को संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के 29वें वर्ष में हरियाणा राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होगी:—

1. संक्षिप्त नाम इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1978 है।

2. 1918 के पंजाब अधिनियम, 6 की धारा 39 का प्रतिस्थापन चंडीगढ़ संघराज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :

39. अधीनस्थ न्यायाधीशों के विरुद्ध अपीलें

(1) पूर्वोक्त के सिवाय किसी अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री या आदेश के विरुद्ध कोई अपील मूल वाद के मूल्य के बावजूद जिला न्यायाधीश को की जा सकेगी।

(2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में किसी अपील की सुनवाई जिला न्यायाधीश या अगर जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

(3) अगर जिला न्यायाधीश केवल ऐसी अपीलों की सुनवाई करेगा, जो उच्च न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करे या जो जिला के जिला न्यायाधीश द्वारा उसे सौंपी जाए।

(4) उच्च न्यायालय में लंबित किसी अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपीलें मूलवाद के मूल्य के बावजूद, ऐसे जिला न्यायाधीश को अन्तर्गत हो जाएंगी, जो साधारण राजपञ्चमीय अधिकारिता प्रयोग कर रहा हो।

(5) उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी मूल वाद में किसी अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित सभी या किन्हीं डिक्रियों या आदेशों के विरुद्ध जिला न्यायाधीश को की गई अपीलों ऐसे अन्य अधीनस्थ न्यायाधीश को जिसे अधिसूचना में उल्लिखित किया जाए, की जाएगी और उस पर अपील तदनुसार पेश की जाएगी तथा अन्य ऐसे अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय को इस प्रकार की गई सभी अपीलों के प्रयोजनार्थ जिला न्यायालय समझा जाएगा।

3. 1918 के पंजाब अधिनियम की धारा 41 का प्रतिस्थापन :—मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"41. द्वितीय अपीलों :—

(1) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा पारित अपील में प्रत्येक डिक्री के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी यदि उच्च

न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मामले में कोई विधिक सारभूत प्रश्न अन्तर्गत है।

(2) इस धारा के अधीन किसी एक पक्षीय पारित अपील डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकेगी।

(3) इस धारा के अधीन किसी अपील में अपील के ज्ञापन में अपील में अन्तर्गत सारभूत विधिक प्रश्न ठीक ठीक वर्णित होगा।

(4) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का कोई सारभूत प्रश्न अन्तर्गत है, वहां वह उस प्रश्न को निश्चित करेगा।

(5) इस प्रकार निश्चित किए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई की जाएगी और प्रत्येकी को, अपील की ऐसी सुनवाई के समय, यह तर्क करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा कि मामले में ऐसा कोई प्रश्न अन्तर्गत अन्तर्गत नहीं है :

परन्तु इस उपधारा की किस्म बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह विधि के किसी अन्य ऐसे सारभूत प्रश्न पर अपील की, जो न्यायालय द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, सुनवाई करने की न्यायालय की शक्ति को, लेखबद्ध कारणों से, हटा लेगी या न्यून कर देगी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अन्तर्गत है।

5. व्यावृत्ति :—इस अधिनियम की धारा 3 में अन्तर्बिष्ट कोई बात किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध किसी ऐसी अपील को, जो इस अधिनियम के आरंभ के पश्चे, स्वीकृत कर ली गई थी, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLI के नियम 11 के अधीन सुनवाई के पश्चात् लागू नहीं होगी या प्रभावित नहीं करेगी, और स्वीकृत कर ली गई ऐसी प्रत्येक अपील का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो ये धाराएं प्रवृत्त ही नहीं हुई थी।

[यू-11015/10/82यू टी एल (175)]

अगोक्त नाथ संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 9th December, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 1158(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966) the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Courts (Haryana Amendment) Act, 1978 (Haryana Act No. 24 of 1978) as in force in the

State of Haryana at the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. In section 2, in the opening portion, for the words and figures "the Punjab Courts Act, 1918" the words and figures "the Punjab Court Act 1918, as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

2. Section 4 shall be omitted.

3. In section 5, in the opening line, the word and figure "and 4" shall be omitted.

ANNEXURE

THE PUNJAB COURTS (HARYANA AMENDMENT) ACT, 1978 (HARYANA ACT NO. 24 OF 1978) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH.

An Act to amend the Punjab Courts Act, 1918, in its application to the State of Haryana.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Punjab Courts (Haryana Amendment) Act, 1978.

2. Substitution of section 39 of Punjab Act 6 of 1918.—For section 29 of the Punjab Court Act, 1918 as in force in the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act), the following section shall be substituted, namely :—

"39. Appeals from Subordinate Judges.—

- (1) save as aforesaid, an appeal from a decree of order of a Subordinate Judge, shall lie to the District Judge, irrespective of the value of the original suit.
- (2) Subject to the provisions of sub-section (3) an appeal to the Court of District Judge shall be heard by the District Judge or by an Additional District Judge.
- (3) An Additional District Judge shall hear only such appeals as the High Court may, by general or special order direct, or as the District Judge of the District may make over to him.
- (4) All appeals from a decree or order of a Subordinate Judge, pending in the High Court, irrespective of the value of the original suit, shall stand transferred to the

District Judge exercising ordinary territorial jurisdiction.

- (5) The High Court may, by notification, direct that appeals lying to the District Judge from all or any of the decrees or orders passed in any original suit by any Subordinate Judge shall be preferred to such other Subordinate Judge as may be mentioned in the notification, and the appeals shall thereupon be preferred accordingly and the Court of such other Subordinate Judge shall be deemed to be a District Court for the purpose of all appeals so preferred."

3. Substitution of section 41 of Punjab Act 6 of 1918.—For section 41 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"41. Second appeals.—(1) An appeal shall lie to the High Court from every decree passed in appeal by any Court subordinate to High Court, if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law.

(2) An appeal may lie under this section from an appellate decree passed ex-parte.

(3) In any appeal under this section the memorandum of appeal shall precisely state the substantial question of law involved in the appeal.

(4) Where the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question.

(5) The appeal shall be heard on the question so formulated and the respondent shall, at the hearing of the appeal, be allowed to argue that the case does not involve such question:

Provided that nothing in this sub-section shall be deemed to take away or abridge the power of the Court to hear, for reasons to be recorded, the appeal on any other substantial question of law, not formulated by it, if it is satisfied that the case involves such question."

4. (Omitted).

5. Saving.—Nothing contained in section 3 of this Act shall apply to or affect any appeal from a decree or order which had been admitted, before the commencement of this Act, after hearing under rule 11 of Order XLI of the Code of Civil Procedure, 1908 and every such admitted appeal shall be dealt with as if these sections had not come into force.

[No. U-11015/10/82-UTL (175)]

ASHOK NATH, Jt. Secy.

